

प्रेषक,

डा० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, चमोली एवं उत्तरकाशी।

ऊर्जा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: २५ मई, 2012

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना लेखानुदान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० को विद्युतीकरण कार्यों (अनुसूचित जनजाति अंश) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० को जिला योजनान्तर्गत (अनुसूचित जनजाति अंश) अनुमोदित कार्यों हेतु ऋण के रूप में ₹ 13.33 लाख (₹ तैरह लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक-1 में वर्णित जनपदवार फीट के अनुसार आपके निर्वर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपदों में वे ही कार्य सम्पादित कराये जायेंगे जो चैलू योजना के हों एवं जनपद की जिला सैक्टर की योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा चयनित एवं अनुमोदित हो। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिचय सीमा के अधीन ही किया जायेगा। व्यय जनपदवार अनुमोदित प्लान परिचय के अनुसार ही किया जायेगा तथा उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 30.03.2012 से जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, संबंधित ग्राम प्रधानों को कार्य कराने से पूर्व व बाद में उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथोचित माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार कर नियमानुसार धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त कार्यों एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेगी।

5- व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैन्युअल, फाईनेन्सियल हैंडबुक, स्टोर पर्चेज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली तथा टेंडर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

6- स्वीकृत कार्यों की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा ऋण रु० 6.5% की दर निर्धारित है। अतः उक्त धनराशि ऋण पर भी ब्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी 10 समान किश्तों में प्रतिवर्ष माह अप्रैल में (ब्याज सहित) की जायेगी तथा प्रथम किश्त की वापसी अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ होगी।

9- प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

10- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० जब भी किश्तों का भुगतान करें ब्याज भी अवश्य जमा करें एवं महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर भेजें:-

1- कोषागार का नाम, 2- चालान सं०, 3- जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4- शासनादेश संख्या और एस०एल०आर० का संदर्भ, 5- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

11- ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से अवश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें।



- 12- भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।
- 13- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 30.03.2013 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का मासिक रूप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- 14- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु व्यय की जायेगी। जिला योजना में सामान्य अंश एवं अनुसूचित जाति अंश के सापेक्ष धनराशि अलग से निर्गत की जा रही है।
- 15- अवमुक्त की जा रही धनराशि का जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य अनुसार व्यय किया जायेगा।
- 16- स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदान सं० 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोगिता -91-यूपीसीएल को ऋण जिला योजना-01-उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं० 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(डा० बी०वी०आर०सी० मुखर्जी)  
अपर सचिव

पत्र संख्या: 792(1)/1(2)/2011-06(1)/35/06, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 4- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 7- सम्बन्धित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, उत्तराखण्ड।
- 8- कोषाधिकारी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, चमोली एवं उत्तरकाशी।
- 9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जिला स्तरीय अधिकारी), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, उत्तराखण्ड द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, देहरादून।
- 10- वित्त अनुभाग-2/बजट निदेशालय।
- 11- समाज कल्याण/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
- 13- विशेष सैल, ऊर्जा।
- 14- गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से

(संजीव कुमार शर्मा)  
अनु सचिव

अनुदान संख्या -31 के लेखा शीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05 -पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोगना-91-यूपीसीएल को ऋण जिला योजना-01-उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण-30-निवेश/ऋण

(धन राशि लाख में)

क्र०स०	जनपद का नाम	वित्तिय वर्ष 2012-13 हेतु जिला योजना में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति उपयोगना के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
1	नैनीताल	2.00
2	पिथौरागढ़	3.33
3	बागेश्वर	2.00
4	देहरादून	2.00
5	चमोली	2.00
6	उत्तरकाशी	2.00
	योग :-	13.33

(तीरह लाख तैंतीस हजार मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)  
अनुसचिव